साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 16-22 मई 2022, वर्ष-8, अंक-7

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

गांवों में हो रही बिजली की कटौती: कृषि मंत्री कमल पटेल ने ऊर्जा मंत्री से फोन पर कहा

प्रद्युम्न सिंह तोमर बोले- हां, व्यवस्था करते हैं और अभी सभी को टाइट करता हूं

चार हजार करोड़ की मूंग को सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिल रही, यदि किसान निपट गया, तो वह हमको भी निपटा देगा

भोपाल। कोयला संकट की वजह से पूरे प्रदेश में बिजली को लेकर हालात बिगड़ गए हैं। इस बीच कृषि मंत्री कमल पटेल का एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें पटेल अपने मोबाइल से हैंड फ्री कर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को हरदा-नर्मदापुरम जिले में लोड सेटिंग के नाम हो हो रही बिजली कटौती को लेकर चिंता जता रहे हैं। अपने बेबाक अंदाज में कृषि मंत्री पटेल ने यह भी बता दिया है कि प्रदेश में किसानों को आज भी बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, कृषि मंत्री ने ऊर्जा मंत्री को यह भी कह दिया कि भाई..दोनों जिलों में चार हजार करोड़ रुपए की मूंग को सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिल रही है, इससे हमारी मूंग खत्म हो जाएगी, यदि किसान निपट गया, तो वह हमको भी निपटा देगा, पीछे से तोमर कहते हैं कि क्या करना है, तब पटेल बोले मैंने बिजली कंपनी के एमडी को बोल दिया है, लेकिन आप थोड़ा टाइट करो।

कार का वीडियो वायरल

वीडियो में मंत्री के साथ कार में बैठा एक व्यक्ति बता रहा है कि बिजली कंपनी लोड सेटिंग के नाम पर भारी कटौती कर रही है। वीडियो देखकर पता चलता है कि यह वीडियो मंत्री के साथ चलती कार में पीछे बैठे व्यक्ति ने ही बनाया है। साथ ही किसानों को उनके प्रयासों की जानकारी देने के लिए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कराया गया है।

तीसरी फसल मूंग

गौरतलब है कि दोनों जिलों में तीसरी फसल मूंग का इस बार बड़े पैमाने पर किसान उत्पादन कर रहे हैं। मंत्री पटेल खुद मूंग के लिए पानी छोड़ने के लिए तवा बांध पहुंचे थे। तवा महोत्सव में उन्होंने स्वयं हरदा- नर्मदापुरम जिले के लिए तय समय से तीन दिन पहले पानी छुड़वा दिया था। हरदा पटेल का गृह जिला है, जो मप्र का एक बड़ा कृषि उत्पादक क्षेत्र है।

मंत्री को सता रही चिंता

कृषि मंत्री को अपने जिले और पड़ोसी जिले की चिंता सता रही है। लगातार दोनों जिलों के किसान और पार्टी कार्यकर्ता, किसान संगठन उन्हें मूंग के लिए पर्याप्त बिजली न मिलने की शिकायत कर रहे हैं। मंत्रियों को डर हैं कि कहीं उन्हें आगामी चुनाव में फसल बिगड़ने का खामियाजा किसानों की नाराजगी के रूप में न उठाना पड़ जाए।

हरदा-होशंगाबाद में 6 घंटे कटौती

सरकार का दावा है कि गांव-खेत में 10 घंटे बिजली मिल रही है। मूंग की फसल के समय किसान को जरूरत पड़ती है। लेकिन हरदा-होशंगाबाद में 4 से 6 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है। मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधीन आने वाले रायसेन, राजगढ़, विदिशा और सीहोर में भी 4 से 5 घंटे की कटौती हो रही है। कस्बाई इलाकों में भी दो घंटे की अघोषित कटौती की जा रही है। भोपाल, इंदौर जैसे बड़े शहरों में एक से दो घंटे की कटौती जारी है। यहां के ग्रामीण इलाकों का हाल भी हरदा-होशंगाबाद जैसा ही है। कटौती 10 से 12 घंटे की हो रही है।

56 हजार हेक्टेयर में गेहूं की खेती में फर्जीवाड़ा

मप्र में 'फर्जी फसल'

» 10 लाख किसानों के सत्यापन में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

भोपाल। संवाददाता

मध्यप्रदेश में गेहूं खरीदी की पूरी प्रक्रिया के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। पंजीयन में जिन किसानों ने अपनी जमीन पर गेहूं बोना बताया है, उस जमीन पर गेहूं की फसल थी ही नहीं। वहां चना या दूसरी फसलें मिलीं। कुछ जगहों पर घर, कहीं नदी-नाले तो कहीं पहाड़ मिले हैं। दरअसल, खाद्य विभाग ने 9 लाख 85 हजार 19 किसानों की 33.69 लाख हेक्टेयर जमीन की मौके पर एसडीएम और तहसीलदार से जांच कराई तो पता चला कि 56 हजार 123 हेक्टेयर जमीन में गेहूं की फर्जी खेती हो रही थी। यहां चौंकाने वाली बात यह है कि आमतौर पर एक हेक्टेयर में औसतन 23 से 25 क्विंटल गेहूं पैदा होता है। जिस 56 हजार हेक्टेयर में गेहूं की बोवनी में गड़बड़ी निकली है, इसी रकबे को आधार बनाकर बिचौलिए व व्यापारी अपना माल खपा देते थे। हर सीजन में यह धंधा 280 करोड़ रुपए से अधिक का होता रहा। किसान गेहूं की बोवनी का जो रकबा सरकार को बताता है, उसी आधार पर सरकार अनुमान लगाती है कि इस सीजन में गेहूं की कितनी पैदावार होगी, लेकिन हाल ही में हुई पड़ताल के नतीजे देखकर गणित गड़बड़ा गया है। यह स्थिति तब है जब 50 फीसदी किसानों की जमीन ही जांच के दायरे में है।

- » गेहूं की बोवनी की नहीं पर फसल बिक गई
- » हर साल बिक जाता था 280 करोड़ का गेहूं
- » नाक के नीचे बिचौलिए कर रहे गेहूं का खेला

कुल पंजीयन 19 लाख के करीब हैं। एसडीएम और तहसीलदार ने एमपी किसान एप पर हुए पंजीयन से जांच की है। इसमें दो हेक्टेयर से अधिक और सिकमी (बटाईदार) किसानों को शामिल किया गया है। अब सभी फसलों की खरीदी से पहले सत्यापन होगा। आधार नंबर का खसरे से मिलान होगा और बैंक खातों को आधार से लिंक किया जाएगा।

सिर्फ पांच जिले सुरक्षित | प्रदेश के सभी 52 जिलों में से सिर्फ पांच ही ऐसे हैं, जहां सत्यापन में पंजीयन के मुताबिक रकबा निलका है। इसमें अलीराजपुर, नीमच, बड़वानी, बालाघाट और बुरहानपुर शामिल हैं। यानी फर्जीवाड़े से यही जिले सुरक्षित पाए गए हैं।

सत्यापन होगा

जिला	जांच वाले किसान	फर्जी रकबा
सिवनी	70,139	6856
सागर	40,131	3044
जबलपुर	31,539	2346
सतना	30,628	3029
छतरपुर	24,679	2051
कटनी	17,538	1324
शिवपुरी	16,021	5265
अशोकनगर	13,841	14467
पन्ना	12,731	3011
ग्वालियर	12,150	5256
भिंड	5,631	2501
मुरैना	3,418	1082

शासन से एक प्रेजेंटेशन हमें मिला है। एसडीएम को मौका मुआयना करने के लिए कह दिया गया है। डैम, पहाड़ के अलावा जहां जंगलों का जिक्र है, हो सकता है वहां खेत हों। वर्ष 2012 के बाद वनाधिकार पट्टे दिए गए हैं। जल्द स्थिति साफ हो जाएगी।

-चंद्रमौली शुक्ला, कलेक्टर, देवास

भोपाल-इंदौर में भी अंतर

भोपाल में 19 हजार 294 पंजीकृत किसानों की जांच की गई, जिसमें सिर्फ 34 हेक्टेयर जमीन का अंतर मिला। इंदौर में 14354 किसानों के वैरिफिकेशन के बाद 14 हेक्टेयर जमीन का अंतर मिला। उज्जैन में 49944 किसानों के सत्यापन में 131 हेक्टेयर जमीन की गड़बड़ी मिली। देवास में कुछ किसानों ने पहाड़ी क्षेत्र, नाले की जमीन पर गेहूं की बोवनी करना बता दिया।

पीएम ने मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति और पोर्टल किए लांच, बोले

स्टार्टअप्स प्राकृतिक खेती के लिए इंदौर को बनाए मॉडल जिला

» भारत की स्टार्टअप क्रांति आजादी के अमृत काल की पहचान बनेगी: मोदी

» अर्थ-व्यवस्था के लिए नई बेकबोन बन रहे हैं स्टार्टअप: सीएम शिवराज

भोपाल। संवाददाता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश की नई स्टार्टअप नीति एवं मप्र स्टार्टअप पोर्टल को दिल्ली से वर्चुअली लांच किया। उन्होंने नए स्टार्टअप चालू करने वाले मप्र के युवाओं इंदौर के तनु तेजस सारस्वत, भोपाल की उमंग श्रीधर एवं इंदौर के तौफिक खान से वर्चुअल संवाद भी किया। तीनों स्टार्टअप्स ने प्रधानमंत्री के साथ अपने कार्य की जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री ने 2 स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता भी ऑनलाइन प्रदान की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में स्टार्टअप की सफलता में सस्ते मोबाइल फोन एवं सस्ते डेटा का महत्वपूर्ण योगदान है। स्टार्टअप और यूनिकार्न आज देश में लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। क्लीन एनर्जी, हेल्थ, टूरिज्म, कृषि, खुदरा व्यापार के क्षेत्र में स्टार्टअप्स उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। मोबाइल गेमिंग के क्षेत्र में आज भारत दुनिया में टॉप 10 में है। टॉयस के ग्लोबल मार्केट में अभी भारत एक प्रतिशत से भी कम पर है, इस क्षेत्र में नौजवानों को आगे आना चाहिए।

किसान स्वाइल टेस्टिंग की ओर ध्यान दें

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इंदौर के स्टार्टअप उद्यमी तौसिफ खान से संवाद के दौरान उन्हें किसानों द्वारा स्वाइल टेस्टिंग किए जाने की ओर ध्यान देने को कहा। तौफिक खान ने बताया कि उनका स्टार्टअप कृषि क्षेत्र में कार्य करता है। किसानों की मिट्टी की जांच के साथ ही उन्हें उर्वरक के समुचित इस्तेमाल की सलाह भी देता है। दवाओं और बीजों की होम डिलीवरी भी करता है। उन्होंने अभी तक 10 हजार किसानों की स्वाइल टेस्टिंग की है। प्रधानमंत्री ने इंदौर जिले को पूर्णरूप से रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती वाला जिला बनाने की दिशा में कार्य करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इंदौर जिले को प्राकृतिक खेती के लिए मॉडल जिला बनाएं।

शहरों को बनाएंगे स्टार्टअप हब

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में इंदौर और भोपाल के साथ ही अन्य शहरों को भी स्टार्टअप हब बनाया जाएगा। सिर्फ आईटी क्षेत्र ही नहीं, जैविक और प्राकृतिक खेती, जिसमें मध्यप्रदेश 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उत्पादन कर अन्य राज्यों से आगे है। स्टार्टअप के लिए अनुकूल है। इसके अलावा कृषि विविधीकरण, एक जिला-एक उत्पाद, सोलर एनर्जी, ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, एनीमेशन, फार्मा सेक्टर, लॉजिस्टिक क्षेत्र सहित कई क्षेत्र हैं, जिनमें कार्य की संभावनाएं उपलब्ध हैं।

मध्यप्रदेश ने ग्रीष्मकालीन मूंग की बोवनी में बनाया रिकॉर्ड

मूंग की फसल से नर्मदांचल के किसान होंगे मालामाल

7 हजार रुपए क्विंटल मिले थे दाम

समर्थन मूल्य पर बीते वर्ष 7 हजार 196 रुपए प्रति क्विंटल के भाव मिले थे। इस बार इससे अधिक में मूंग बिकने की संभावना है। इसलिए पिछले वर्ष से ज्यादा राशि किसानों के खाते में आएगी जिसका लाभ व्यापारियों तथा बाजार में भी होता है किसान के पास नकद राशि आने पर उनके द्वारा खरीदी करने से बाजार में भी ग्राहकी का असर बढ़ता है।

तवा की दम पर अधिक बोवनी

वरिष्ठ किसान सुदीप पटेल का कहना है कि ग्रीष्म कालीन मूंग की फसल पूरी तरह पानी पर निर्भर रहती हैं। 60 दिन की फसल को लगातार कम से कम 30 दिन पानी चाहिए। तवा बांध से भरपूर पानी मिलता हैं। इसके साथ ही किसानों ने पिछले 10 वर्षों में अपने खेतों में जो ट्यूबवेल तैयार किए हैं उसका भी परिणाम है कि मूंग की भरपूर खेती होने लगी है।

इस बार मिल रहा पर्याप्त समय

इस बार अधिकांश किसानों ने पूर्व से ही मूंग की बोवनी करने के लिए चना की बोवनी की थी जिससे चना की फसल जल्दी कट जाने से किसानों को मूंग की बोवनी करने में पर्याप्त समय मिला है जिन किसानों ने गेहूं की बोवनी की थी उन्होंने भी गेहूं की फसल काटने के तुरंत बाद मूंग की बोवनी कर दी है उनकी फसल भी इस समय ठीक स्थिति में है।

इस बार पिछले वर्षों की तुलना में सबसे अधिक मूंग की बोवनी हुई है। कुल 2 लाख 32 हजार हेक्टेयर में बोवनी हुई है। फसल भी अच्छी है। किसानों की कड़ी मेहनत, तवा बांध से निरंतर पानी का मिलना, समय पर खाद तथा बिजली मिलने से मूंग की फसल लहलहा रही है। इस बार भी मूंग की पैदावार अच्छी होने की संभावना बन रही है।

जेआर हेड़ाउ, उप संचालक कृषि, नर्मदांचल

पिछले वर्ष जिले के किसानों ने 10 अरब की बेची थी मूंग

नर्मदापुरम। संवाददाता

खाद्यान्न, सोयाबीन, धान की भरपूर पैदावार करने वाले नर्मदापुरम जिले ने इस बार अपने पुराने सभी रिकार्ड तोड़ते हुए ग्रीष्म कालीन मूंग की बोवनी का सबसे अधिक बोवनी का रिकॉर्ड बना लिया है। प्रदेश ही नहीं, देश में सबसे अधिक ग्रीष्म कालीन मूंग की बोवनी हुई है। इस बार जिले में 2 लाख 32 हजार हेक्टेयर में मूंग की बोवनी हुई है। तवा बांध से सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलना तथा असिंचित क्षेत्र वाले इलाकों में ट्यूबवेल से भरपूर सिंचाई हो रही है। इस बार की फसल बीते वर्षों से अच्छी बताई जा रही है। रोग भी कम ही लग रहा है। बोवनी समय पर होने से कटाई के लिए भी पर्याप्त समय मिलने की उम्मीद किसानों को बनी हुई है किसानों का अनुमान है कि इस बार फसल अच्छी होने से पिछले वर्षों से अधिक पैदावार होने की संभावना है। पिछले वर्ष जिले के किसानों ने 10 अरब रुपए की मूंग बेची थी। इस बार उससे भी ज्यादा का लाभ होने की संभावना बन रही है।

बीते वर्ष 2 लाख 8 हेक्टेयर में थी फसल

बीते वर्ष किसानों ने 2 लाख 8 हजार हेक्टेयर में मूंग की बोवनी हुई थी। इस बार 24 हजार हेक्टेयर ज्यादा में बोवनी हुई है। पिछले वर्ष सरकारी रिकार्ड में 9 अरब 40 करोड़ की मूंग खरीदी हुई थी। 80 हजार 612 किसानों ने मूंग की फसल लगाई थी उससे पूर्व 2020 में 1 लाख 82 हजार 200 हेक्टेयर क्षेत्र में मूंग की फसल ली गई थी। जो बारिश जल्दी आने के कारण कई किसानों की मूंग खराब हो गई थी।

वनग्रामों के निवासियों को नहीं झेलना पड़ेगा विस्थापन का दर्द

राजस्व ग्राम से मुख्य धारा में आएंगे पिछड़े वनवासी

भोपाल। संवाददाता

राज्य सरकार द्वारा 827 वनग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने के निर्णय से इनके निवासियों की विस्थापन की समस्या खत्म हो गई है। राजस्व ग्राम का दर्जा मिलते ही इन गांवों में विकास कार्यों के रास्ते खुल गए हैं। खासकर पक्के मकान बनाने पर कोई रोक-टोक नहीं होगी। अनुमति लेकर नियमानुसार कोई भी मकान बना सकेगा। इस निर्णय से ग्रामीणों को तो लाभ होगा ही, केंद्र और राज्य सरकार को भी फायदा हुआ है। शासन को इन गांवों से ग्रामीणों के विस्थापन के लिए राशि खर्च नहीं करनी पड़ेगी और दूसरी जगह बसाने के लिए भूमि का इंतजाम भी नहीं करना होगा। प्रदेश के 29 जिलों में 925 वनग्राम हैं। ये 240431.220 हेक्टेयर में बसे हैं। जिनमें 19,782 पट्टेधारी हैं। इनमें से 827 ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित कर दिया गया है। यानी अब मौजूद वनग्रामों के निवासियों को विस्थापन का दर्द नहीं झेलना पड़ेगा।

प्रदेश के वन ग्राम वाले जिले

जिला	वनग्राम	रकबा
बुरहानपुर	102	40005.538
बैतूल	92	16233.439
डिंडोरी	86	32465.977
मंडला	84	19235.946
बालाघाट	70	11456.184
बड़वानी	70	15846.447
खरगोन	67	32646.880
सीहोर	53	7554.425
होशंगाबाद	52	7374.260
छिंदवाड़ा	49	7828.364
हरदा	42	14307.720
सिवनी	28	5923.930
रायसेन	18	2547.272
कुल	संख्या	हेक्टेयर में

केंद्र सरकार की अनुमति और भूमि डि-नोटिफाई किए बगैर कोई विस्थापित ग्रामीणों को कोई विशेष फायदा नहीं होगा।

जेपी शर्मा, सेवानिवृत्त, वन अधिकारी

सरकार की बसाएगी

हालांकि यह रास्ता भी खुला रहेगा कि निवासी मर्जी होने पर विस्थापन की सहमति दे सकते हैं। सरकार उन्हें उपयुक्त स्थान तलाशकर बसाएगी। अभी तक ज्यादातर मामलों में ग्रामीण गांव नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनका भावनात्मक जुड़ाव होता है। गौरतलब है कि अभी सरकार दो साल में विस्थापन में करीब सौ करोड़ रुपए खर्च कर देती है। इसके लिए एक परिवार को 15 लाख दिए जाते हैं।

ग्रामीणों को लाभ

भूमि की खसरा-खतौनी, अक्स बन जाएंगे। भू-अभिलेख व्यवस्थित हो जाएगा। फोती, नामांतरण-बंटवारा, भूमि संबंधी विवाद सुलझाए जा सकेंगे। प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने या अन्य नुकसान होने पर मुआवजा मिलने लगेगा।

भूमि का वैधानिक स्वरूप नहीं बदलेगा

सरकार ने वन अधिकार अधिनियम-2006 की धारा-तीन के तहत वनग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने का रास्ता निकाला है। इसमें प्रावधान है कि भूमि का वैधानिक स्वरूप बदले बगैर अधिकार दिए जा सकते हैं। इस भूमि को बेचा नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल पार्क से भूमि डि-नोटिफाई करने के अधिकार राष्ट्रीय वन्यप्राणी मंडल को दे दिए हैं। सामान्य वनमंडल की सीमा में स्थित ग्रामों के मामले में ऐसे ही अधिकार केंद्र सरकार लेना चाहती है। यह प्रक्रिया चल रही है।

दुश्मन से ज्यादा नीलगाय सिरदर्द, अब मारने का भेजा प्रस्ताव

देश के दूसरे सबसे बड़े एयरबेस पर 150 नीलगाय का कब्जा

ग्वालियर। संवाददाता

देश के सबसे बड़े दूसरे एयरबेस पर फिलहाल दुश्मन से ज्यादा नीलगाय सिरदर्द बन गई हैं। महाराजपुरा स्थित एयरफोर्स कैंपस में 150 नीलगाय हैं, जिनकी पहुंच आवासीय परिसर तक हो गई है। एयरफोर्स के विमानों की उड़ानों के दौरान नीलगाय रन-वे पर न आ जाएं इसे रोकने के लिए एयरफोर्स में अलग से कर्मचारी तैनात करने पड़ रहे हैं। वहीं विमानों को नुकसान व हादसे का खतरा भी रहता है। यही कारण है कि अब नीलगाय से निपटने के लिए मारने तक की अनुमति का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। हाल ही में एयरफोर्स के अफसरों, प्रशासन और वन विभाग के साथ बैठक हुई। जिसमें एयरबेस पर नीलगाय की गंभीर समस्या को सामने रखा गया। इस प्रस्ताव पर प्रशासन व वन विभाग ने मारने की अनुमति को विकल्प बताया है, जिसके लिए अब प्रस्ताव केंद्र स्तर पर भेजा जाएगा। बैंगलुरू के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा एयरबेस ग्वालियर ही है। यहां सामरिक महत्व के दृष्टिकोण से अहम विमान व संसाधन हैं। कुछ समय पहले हुई सर्जीकल स्ट्राइक में भी ग्वालियर एयरबेस ने अपनी भूमिका निभाई थी। ग्वालियर एयरबेस काफी बड़े हिस्से में फैला हुआ है। इसका मुख्य एरिया, आवासीय एरिया के साथ जंगल क्षेत्र भी है, जहां हरियाली काफी है। इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा नीलगाय हैं, जो पूरे एयरबेस परिसर में निकलती रहती हैं। तार फेंसिंग से लेकर बाउंड्रीवाल तक को नीलगाय नुकसान पहुंचा रही हैं। एयरफोर्स के महत्वपूर्ण विमानों को रन-वे पर काफी ध्यान रखना पड़ता है। एयरफोर्स के जंगल क्षेत्र से नीलगाय आ जाती हैं। अभी तो छोटी बाउंड्री है वह तोड़ देती हैं और फेंसिंग भी नहीं रोक पा रही है। वन विभाग ने बड़ी और पक्की बाउंड्री बनाकर रोके जाने का भी विकल्प दिया है।

अभी बिहार में मारने की अनुमति

नीलगाय को मारने की अनुमति अभी बिहार में है। बिहार में नीलगाय व जंगली सुअर को मारा जा सकता है। मप्र में जनवरी में राज्य सरकार की ओर से नीलगाय व जंगली सुअर को मारने की अनुमति का प्रस्ताव बनाया गया है, जिस पर सुझाव लिए जा रहे हैं, निर्णय होना बाकी है। किसानों की फसल खराब कर देने के कारण नीलगाय परेशानी का कारण हैं। प्रदेश में वर्ष 2000 और 2003 में नीलगाय व जंगली सुअर के शिकार पर सख्ती करने के लिए निर्णय लिए गए थे, इसके बाद से कोई नीलगाय नहीं मारी गई।

इसलिए खतरनाक नीलगाय

नीलगाय एक बड़ा और शक्तिशाली जानवर है। कद में नर नीलगाय घोड़े जितना होता है, पर उसके शरीर की बनावट घोड़े के समान संतुलित नहीं होती। पृष्ठ भाग अग्रभाग से कम ऊंचा होने से दौड़ते समय यह अत्यंत अटपटा लगता है। नीलगाय भारत में पाई जानेवाली मृग जातियों में सबसे बड़ी है। इसका वजन 120 किलो से 240 किलो तक होता है और हाइवे पर सड़क हादसों का भी बड़ा कारण है।

नीलगाय को मारने की अनुमति अभी यहां नहीं है। एयरफोर्स परिसर में काफी संख्या में नीलगाय हैं, जिसके कारण एयरफोर्स के विमानों की उड़ान के दौरान खतरा हो सकता है, यह भारी जानवर है। एयरफोर्स को बाउंड्रीवाल बनाने का भी विकल्प दिया है। मारने का भी विकल्प है, जो प्रस्ताव में शामिल किया गया है।

ब्रजेन्द्र श्रीवास्तव डीएफओ, ग्वालियर

एक दिन के कड़कनाथ चूजों की कीमत 75 रुपए

कड़कनाथ की फार्मिंग करेंगे धोनी मध्यप्रदेश से दो हजार चूजे खरीदे

कानूनी लड़ाई के बाद 2018 में GI टैग मिला

भोपाल। संवाददाता

क्रिकेट में अपनी धुआंधार बल्लेबाजी और कुशल नेतृत्व के लिए पहचाने जाने वाले पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मध्य प्रदेश के खास कड़कनाथ मुर्गों की फार्मिंग करने जा रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी के ऑर्डर पर झाबुआ जिले से कड़कनाथ नस्ल के दो हजार चूजों को हाल ही में रांची के लिए रवाना किया गया है। मध्य प्रदेश स्थित एक सहकारी समिति ने धोनी के ऑर्डर पर उच्च प्रोटीन के लिए प्रसिद्ध कड़कनाथ नस्ल के 2,000 चूजों को झारखंड के रांची के एक फार्म में भेजा है। एक दिन के कड़कनाथ चूजों की कीमत करीब 75 रुपए है, जबकि 15 दिन और 28 दिन के चूजों की कीमत क्रमश: 90 रुपए और 120 रुपए है।

लंबी कनूनी लड़ाई के बाद 2018 में मिला जीआई टैग

गौरतलब है कि झाबुआ जिले के काले कड़कनाथ चिकन मांस को छत्तीसगढ़ के साथ कानूनी लड़ाई के बाद 2018 में जीआई टैग मिला। जीआई टैग भौगोलिक क्षेत्र से आने वाले विशेष उत्पाद को दर्शाता है। इसके वाणिज्यिक मूल्य को बढ़ाता है। कड़कनाथ मुर्गी के अंडे और मांस अन्य नस्लों की तुलना में अधिक दर पर बेचा जाता है।

- पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने स्थानीय सहकारी से मंगवाए गए 2,000 कड़कनाथ चूजों को एक वाहन से उनके गृह नगर रांची भेजा गया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है कि धोनी जैसे लोकप्रिय व्यक्तित्व ने कड़कनाथ चिकन किस्म में रुचि दिखाई है। कोई भी इन हैचलिंग को ऑनलाइन मोड के माध्यम से ऑर्डर कर सकता है, इससे जिले के आदिवासी लोगों को फायदा होगा।

सोमेश मिश्रा, कलेक्टर, झाबुआ

- भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ समय पहले कड़नाथ के चूजों का ऑर्डर दिया था, लेकिन उस समय बर्ड फ्लू फैलने के कारण चूजों की आपूर्ति नहीं की जा सकी थी। मध्य प्रदेश सरकार ने 2018 में एक कड़कनाथ ऐप लॉन्च किया था ताकि लोग ऑनलाइन माध्यम से चूजों को ऑर्डर कर सकें। धोनी की इस पहल से और भी लोग सामने आएंगे। वैसे भी कड़कनाथ की काफी डिमांड है।

डॉ. आईएस तोमर, प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद, झाबुआ

- महेंद्र सिंह धोनी ने हमें ऑर्डर दिया था। रांची भेजे गए सभी 2,000 कड़कनाथ चूजों को टीका लगाया गया है। धोनी के प्रबंधक ने हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि क्रिकेटर के फार्म हाउस में चूजों के पालन की सुविधा विकसित की गई है। हम झाबुआ की आदिवासी संस्कृति के प्रतीक के रूप में धोनी को एक पारंपरिक धनुष और तीर भी भेंट करेंगे।

विनोद मेदा, सहकारी संस्था, झाबुआ

भोपाल के आसपास हरियाली बढ़ाने की कवायद

17 नर्सरियों में 70 लाख पौधे तैयार

भोपाल। भोपाल वन वृत्त की 17 नर्सरियों में 70 लाख पौधे तैयार किए जा रहे हैं। ये भोपाल समेत आसपास के सीहोर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ में हरियाली बढ़ाएंगे। इनका रोपण बारिश की शुरुआत के साथ किया जाएगा। सबसे अधिक सागौन के पौधे लगाए जाएंगे, क्योंकि नर्सरियों में इस प्रजाति के पौधे ही अधिक तैयार किया जा रहे हैं। सागौन की लकड़ी काफी कीमती होती है। वन विभाग तो इसका रोपण करता ही है, अब निजी, सामाजिक संस्थाएं, किसान भी इसे लगा रहे हैं। इसके अलावा पीपल, बरगद, आंवला, करंज, नीम, बांस प्रजाति के पौधे भी तैयार किए जा रहे हैं। सीताफल जैसे फलदार पौधे भी तैयार किए जा रहे हैं। पहली बार इन नर्सरियों में विलुप्त प्रजाति मे शामिल बीजा, तींसा, गुरुड़ फल, सोनपाठा समेत आठ प्रजाति तैयार की जा रही है।

प्रदेश में चार करोड़ पौधे

भोपाल की अहमदपुर, भदभदा व इमलिया मुख्य नर्सरी है। इसके अलावा आसपास बांसापुर, थूना, हलाली, रंगई, बैस समेत 17 नर्सरी है। ये सभी वन विभाग के अतंर्गत सामाजिक वानिकी की नर्सरी है। इनमें पौधों को तैयार किया जा रहा है। वहीं प्रदेश में 173 नर्सरियां हैं। इनमें करीब चार करोड़ पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इनमें से 75 प्रतिशत पौधे जंगलों में लगाए जाने की योजना है।

45 लाख पौधे वन विभाग लगाएगा

नर्सरियों में तैयारिया किए जा रहे करीब 45 लाख पौधे वन विभाग अपने-अपने जंगलों में लगाएगा। बचे पौधे निजी, सामाजिक संस्था, अन्य शासकीय विभाग, एजेंसियां, किसान और इच्छुक लोगों को बेचे जाएंगे। संभावित मांग के अनुरुप हर वर्ष इतने पौधे तैयार किए जाते हैं। सामाजिक वानिकी को इसके लिए बजट मिलता है।

ये भी खरीदते हैं पौधे

भारतीय सेना समेत विभिन्न सुरक्षा बलों द्वारा पौधे की मांग की जाती रही है, जो इस बार अधिक है। इसके अलाव पंचायतें, एनजीओ, रेलवे भी पौधे खरीदता है। सामाजिक वानिकी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सभी की संभावित जरुरतों को देखते हुए पौधे तैयार किए जा रहे हैं।

- जंगलों की जरुरतों व निजी क्षेत्रों में लोगों की मांग को देखते हुए भोपाल क्षेत्र की 17 नर्सरियों में 70 लाख पौधे तैयार कर रहे हैं। ऐसी प्रजातियों को भी शामिल किया है जो कम मिलती है या मिलती ही नहीं हैं।

- एचसी गुप्ता, सीसीएफ, सामाजिक वानिकी, भोपाल वृत्त

अपने खेत में तालाब बनाओ एक लाख का अनुदान पाओ

भोपाल। संवाददाता

बलराम योजना के अंतर्गत किसान स्वयं की जमीन पर तालाब का निर्माण करा सकते हैं। तालाब बनाने पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किसानों को एक लाख रुपए, लघु और सीमांत किसानों को 80 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को किसी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वे स्वयं की जमीन पर तालाब निर्माण करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निर्माण के बाद सिंचाई के लिए ड्रिप या स्प्रिंकलर लगाना अनिवार्य होगा। किसान द्वारा निर्धारित किए गए निर्माण स्थल का अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने के बाद ही स्वीकृति प्रदान की जाएगी। किसान अपनी जमीन पर तालाब का निर्माण कराकर एक ओर जहां जल संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा दे सकते हैं। वहीं दूसरी ओर उन्हें सिंचाई की भी सुविधा प्राप्त होगी।

1 लाख या 75 प्रतिशत मिलेगा अनुदान

शासन द्वारा किसानों के लिए बलराम तालाब योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत खेतों में जल संरक्षित करने, कृषि कार्यों को सुचारू रूप से चलाने, मछली पालन आदि किया जा सकता है, इस योजना के तहत अगर कोई किसान अपने खेत में तालाब खुदवाता है, तो सरकार उसे पात्र होने पर योजना के तहत 75 प्रतिशत अनुदान या अधिकतम 1 लाख रुपए तक का अनुदान देगी, जिससे तालाब निर्माण का खर्च लगभग शून्य रह जाएगा।

बलराम तालाब योजना

बलराम तालाब योजना के तहत किसानों को सहयोग प्रदान करने के लिए सरकार सब्सिडी प्रदान करती है, ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ लेकर अपने खेतों में तालाब का निर्माण करवाएं, क्योंकि खेतों में तालाब खुदने से निश्चित ही उस क्षेत्र का जल स्तर सुधरेगा, इससे जहां किसानों को सिंचाई करने में आसानी होगी, वहीं दूसरी और आसपास के क्षेत्र में भी नमी बनी रहेगी।

किसान ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन

योजना के तहत किसान तालाबों में वर्षा के जल को संग्रहित कर अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। किसान इस योजना का लाभ लेकर सिंचाई के लिए पानी की समस्या दूर कर सकते हैं, इसी के साथ विभिन्न प्रकार की फसलें उगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। इस योजना को और भी सफल बनाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने प्रदेश में पहले से चल रही बलराम ताल योजना को भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत शामिल कर लिया है। जिसके तहत आप भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

जमीन और मिट्टी की भी जरूरत नहीं

अब एरोपोनिक पद्धति से उगाए जाएंगे आलू

भोपाल। संवाददाता

प्रदेश की पहली एरोपोनिक तकनीक की यूनिट ग्वालियर में स्थापित होगी। इसकी कागजी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रदेश के उद्यानिकी विभाग और इसे तैयार करने वाली एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के बीच दिल्ली के कृषि भवन में इसके लिए करार हो चुका है। इस तकनीक से आलू उगाने का फायदा ये है कि इसके लिए जमीन और मिट्टी की जरूरत नहीं होगी। आलू की खेती हवा में होगी और बीज भी तैयार किए जा सकेंगे। ग्वालियर में यूनिट स्थापित होने के बाद प्रदेश के किसानों को यहां से अलग-अलग किस्म के आलू, बीज और एरोपोनिक तकनीक सांझा की जाएगी। एरोपोनिक तकनीक का प्रयोग आलू बीज ट्यूबर के उत्पादन के लिए किया जाएगा। इस तकनीक से प्राप्त होने वाले पौधों का किसान बिना मिट्टी के भी फसल में उपयोग कर सकते हैं। इस तकनीक से फसल के उत्पादन में भी करीब 12 फीसद तक बढोत्तरी होगी। इससे किसानों को कम लागत में अधिक फायदा होगा। दरअसल, देश में आलू की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अनुपात में आलू का उत्पादन नहीं हो रहा है।

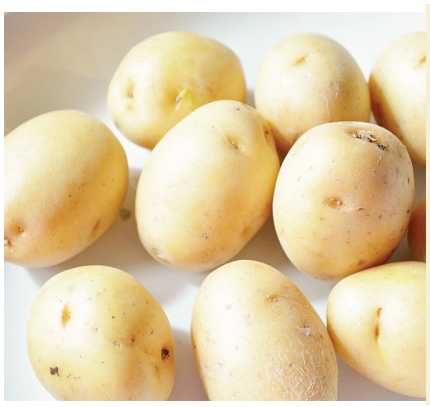

बदलेगा खेती का तरीका

किसान अब भी परंपरागत तरीके से ही खेती कर रहे हैं, इसलिए नतीजे उम्मीद के अनुसार नहीं मिलते हैं। इस नई तकनीक से किसानों की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। इस तकनीक में पाली हाउस में खेती होती है। इसमें आलू के पौधे ऊपर की तरफ होते हैं। जबकि उनकी जड़ें जमीन की तरफ अंधेरे में लटकी रहती हैं। इसमें पानी देने के लिए नीचे पानी के फुव्वारे लगाए जाते हैं।

किसानों को मिल रहा लाभ

पानी में न्यूट्रिएंटस भी मिलाए जाते हैं। इससे ऊपर से जहां पौधों को धूप मिलती है। वहीं नीचे से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। गौरतलब है कि इसके पहले भी ग्वालियर में आलू अनुसंधान केंद्र में कई प्रकार की आलू की प्रजातियों के बीजों की वैरायटियां तैयार की गई हैं। जिसका किसानों को काफी लाभ भी मिला है।

पारंपरिक फसलें विलुप्ति होने के कगार पर

रोहणी प्रसाद पांडेय
वरिष्ठ समाज सेवी एवं चिंतक

पारंपरिक फसलों के संरक्षण के बावजूद दुनिया भर के जीन बैंकों में 25 प्रमुख फसलों की पारंपरिक किस्मों के वैश्विक विश्लेषण से पता चला है कि उनके संरक्षण की दिशा में आधी सदी से जबरदस्त प्रगति हुई है। जबकि इनमें सबसे महत्वपूर्ण किस्मों की पहचान भी की गई है। अभी भी फसलों की कई किस्मों को सामने लाना बाकी है। अध्ययनकर्ताओं की एक टीम ने अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर सीजीआईएआर के केंद्रों की यात्रा में तीन साल बिताए, जिनमें से हर एक ने गेहूं, धान, मक्का, आलू, बीन्स और कसावा जैसी फसलों के विशाल जीन बैंक संग्रह बनाए।

अध्ययनकर्ताओं इस बात का आकलन किया कि इस तरह के संग्रह किस हद तक अलग-अलग तरह की कृषि भूमि के लिए सही होंगे। यह अध्ययन कॉलिन खौरी की अगुवाई में किया गया है। खौरी एलायंस ऑफ बायोवर्सिटी इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर के शोधकर्ता और सैन डिएगो बोटैनिकल गार्डन में विज्ञान और संरक्षण के निदेशक हैं। अध्ययनकर्ताओं ने बताया कि ये प्रजातियां उनके जंगली रिश्तेदारों से मेल खाती हैं। फसल उगाने वालों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक हैं। क्योंकि प्रत्येक बीज में विशेष कीटों और रोगों के प्रतिरोध, सूखे या गर्मी या ठंड या नमकीन मिट्टी में उगने और विभिन्न स्वाद और पोषण सहित इनमें कई लक्षण होते हैं। पिछले 100 वर्षों में दुनिया भर में हुए भारी पर्यावरणीय और सामाजिक बदलावों के कारण, कई किसान अब इन किस्मों को नहीं उगाते हैं और कई आवास जहां इन फसलों के जंगली रिश्तेदार कभी रहते थे अब वे पूरी तरह से बदल गए हैं। पिछले 50 वर्षों में बीजों के संरक्षण को सुनिश्चित करने और फसल प्रजनन उनकी उपलब्धता को बढ़ाने के लिए जीन बैंकों का उपयोग किया गया। जीन बैंकों में बीजों के रखरखाव करने के लिए व्यापक वैश्विक प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों ने अंतरराष्ट्रीय जीन बैंकों की स्थापना के साथ-साथ राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अन्य संग्रहों की स्थापना की। इन जीन बैंकों में से एक फ्यूचर सीड्स है, जिसका उद्घाटन कोलंबिया के पामिरा में हुआ था। हालांकि ये प्रयास किस हद तक फसलों की प्रजातियों को इकट्ठा करने और संरक्षित करने में सफल रहे हैं, इसका मूल्यांकन पहले नहीं किया गया। फसल उनके जंगली रिश्तेदारों के जीन बैंकों का एक वैश्विक विश्लेषण 2016 में पूरा किया गया था, जिसे नेचर प्लांट्स में भी प्रकाशित किया गया था। भू-प्रजातियों पर यह नया शोध दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से 25 के भीतर आनुवंशिक विविधता के संरक्षण करना है। खौरी ने कहा कि अब हम जो जानते हैं वह यह है कि पारंपरिक किसानों की फसल की किस्मों की विविधता का लगभग दो तिहाई, औसतन हमने जिन 25 फसलों का अध्ययन किया है, वे पहले से ही जीन बैंकों में रखी गई हैं। अध्ययन में पाया गया कि ब्रेडफ्रूट, केला और प्लाण्टेंस, दाल, कॉमन बीन्स, चिकपीस, जौ और गेहूं जैसी फसलें भूमि की विविधता के मामले में जीन बैंकों में सबसे अधिक संरक्षित की गई हैं, जबकि फसलों की सबसे बड़ी संरक्षण की कमी हमेशा बनी रहती है। अध्ययन में इन 25 फसलों के लिए भूमि में सबसे बड़ी विविधता वाले दुनिया के क्षेत्रों की भी पहचान की गई, जिसमें बांग्लादेश, इथियोपिया, भारत, नेपाल और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों के साथ-साथ दक्षिण अफ्रीका, मध्य एशिया, भूमध्यसागरीय, पश्चिम एशिया के क्षेत्र, पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के इंडियन पर्वत और मेसोअमेरिका के इलाके शामिल थे। खौरी ने कहा दुनिया के फसल संरक्षणवादियों ने पिछली आधी सदी में बहुत काम किया है और अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। लेकिन मुझे यह जानकर राहत मिली कि जीन बैंकों में फसल विविधता का संरक्षण हमारे मुकाबले कहीं आगे की सोच रखती है। हालांकि यह कहते हुए कि केवल जीन बैंकों में फसलों का भंडारण करना पर्याप्त नहीं है। फसलों को कीटों और बीमारियों और जलवायु परिवर्तन के साथ विकसित करना जारी रखने के लिए, अलग-अलग तरह की फसलों की खेती करना आवश्यकता है। इस शोध के परिणामों का उपयोग अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय भागीदारों को शामिल करने की योजना के लिए किया जा रहा है। जो वर्तमान में महत्वपूर्ण संरक्षण वाले 10 देशों में एकत्रित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जंगली रिश्तेदारों पर पिछले शोध के साथ, जिसमें 2015-2021 तक जीन बैंकों में संरक्षण के लिए 4,500 से अधिक नए नमूनों के संग्रह की योजना बनाने में मदद की, आगामी कुछ वर्षों में भूमि के काफी संग्रह के लिए उम्मीदें बहुत अधिक हैं। अध्ययनकर्ता ने कहा अभियान शुरू करने से पहले, हमें यह जानने की जरूरत है कि हमने पहले किसी फसल को कहां एकत्र किया है और फसलों की विविधता में अभी भी कहां कमी है। नाइजर में आईसीआरआईएसएटी एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां लोबिया, बाजरा और ज्वार में जबरदस्त विविधता है। एलायंस ऑफ बायोवर्सिटी इंटरनेशनल और सीआईएटी में आनुवंशिक संसाधन वैज्ञानिक जूली सरडोस, जो छह वर्षों से अधिक समय से केला संग्रह मिशन चला रही हैं, वे कहती हैं कि उनके काम का एक उल्लेखनीय उदाहरण कुक आइलैंड्स में 'फी' केले है, जिसे उन्होंने 2019 में एकत्र किया था। उन्होंने बताया कई किसान जिनसे हम मिलते हैं, वे अच्छी तरह जानते हैं कि उनके कुछ पारंपरिक भू-प्रजातियां उत्तरोत्तर लुप्त होती जा रही हैं। ज्यादातर जलवायु और सामाजिक कारकों से जुड़े परिवर्तनों से फी केला एक प्रतिष्ठित पोलिनेशियन फसल है जिसमें बड़ी क्षमता है। उनके संतरे के फलों में प्रो-विटामिन ए का स्तर बहुत अधिक होता है। उन्होंने कहा लेकिन कुक आइलैंड्स में हमने जो फी केले का बीज एकत्र किया था, उनमें से प्रत्येक की खेती केवल एक व्यक्ति द्वारा की जा रही थी, ज्यादातर मृतक रिश्तेदार की याद में और ये किसान अपने पूर्वजों की विरासत को गायब होते हुए देखकर चिंतित थे। एक जोड़े के बाद वहां केले इकट्ठा करने के दिनों में, मैंने उनकी चिंताओं को भी साझा किया, जिन युवाओं से हम मिले उनमें से अधिकांश को बमुश्किल पता था कि 'फी' केले खाने योग्य है। यह अध्ययन नेचर प्लांट्स पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

मध्यप्रदेश में फिर लौटेगा गौ-सदनों का वैभव

स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरि
अध्यक्ष (कार्यपरिषद) मप्र गौ-पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड

मध्यप्रदेश गायों एवं गायों की संतानों (बछड़े-बछड़ियों, सांड-बैलों) के संरक्षण के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य है। यहां का 951 हजार वर्ग किलो मीटर का जंगल गौ-वंश का आश्रय-स्थल है। सृष्टि के प्रारंभ से ही प्रकृति और मूक-प्राणियों के मध्य एक नैसर्गिक समीकरण बना हुआ है। गायों का भोजन जंगल में और गोबर एवं गौ-मूत्र के रूप में जंगल का आहार गायों के पास।

शासन-प्रशासन और आम नागरिकों को मिलकर इस प्राकृतिक समीकरण के आधार पर गौ-वंश के संरक्षण एवं पालन की दिशा में युगानुकूल सम-सामयिक और नवाचार विधि से कार्य करना चाहिये। अविभाजित मध्यप्रदेश के जंगलों में वर्ष 1916 से 10 गौ-सदन होते थे। वर्षा काल में लगभग तीन माह गौपालकों-कृषकों का पालित गौ-वंश जंगलों में बने इन्हीं 10 गौ-सदनों में निवास करता था। दीपावली के आसपास इन गौ-सदनों से कृषकों-गौ-पालकों का गौ-वंश सकुशल घर वापस आ जाता था। प्राचीन भारत का यह किसानों की फसल सुरक्षा एवं गौ-वंश के संरक्षण का पारम्परिक रोडमेप हुआ करता था। ये गौ-सदन वर्ष 2000 तक व्यवस्थित संचालित होते रहे।

गौ-सदनों के पास जंगलों में 7200 एकड़ चरनोई भूमि होती थी। वन विभाग की इस भूमि पर राज्य के पशुपालन विभाग का आधिपत्य रहा। मध्यप्रदेश का विभाजन होने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया और दो गौ-सदन (बिलासपुर और रायपुर के) छत्तीसगढ़ राज्य के हिस्से में चले गये। दुर्भाग्य से मध्यप्रदेश के 8 गौ-सदन अकारण ही भंग कर दिये गये। मध्यप्रदेश में गायों के समक्ष समस्या तब पैदा हुई जब मध्यप्रदेश के वर्ष 2000 और वर्ष 2003 के कालखंड के तत्कालीन शासन ने चरनोई भूमि की बंदरबांट मनुष्यों में कर दी। जंगलों के गौ-सदन के भंग होने एवं नगरों और ग्रामों की चरनोई भूमि का मनुष्यों में आवंटन ने मूक-प्राणियों, गौ-वंश आदि के जीवन को संकटग्रस्त कर दिया। इधर, तत्कालीन केंद्र शासन और राज्य शासन की मांस निर्यात नीति एवं कत्लखानों को धड़ल्ले से लाइसेन्स जारी करने की नीति ने प्रदेश के गौ-वंशीय तथा अन्य कृषिक पशुधन की महती हानि कर डाली। प्रदेश में विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक सामाजिक एवं अन्यान्य संगठनों के सम्मिलित आंदोलन, अनुष्ठान अभियान और प्रयासों से प्रदेश में पशुवध रोकने के कड़े कानून बने। आयोगों का गठन हुआ। मध्यप्रदेश गौ-पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड बना। मालवा क्षेत्र के एक विशाल भू-खंड में कामधेनु गौ-अभयारण्य का निर्माण हुआ। प्रदेश के मध्यभारत, बुंदेलखंड, बघेलखंड एवं महाकोशल क्षेत्र में भी हमने मालवा क्षेत्र की भांति अपने प्रयास संभावना के आधार पर आरम्भ कर दिए हैं। प्रदेश में शासन की संकल्प शक्ति, प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग और सक्रियता से तथा स्वयं सेवी संगठनों एवं संस्थाओं के प्रयत्नों से 627 स्वयं सेवी संगठनों की गौ-शालाएं और 1265 गौ-शालाएं मनरेगा के आर्थिक सहयोग से निर्मित ग्राम पंचायत स्तर पर क्रियाशील हो गई हैं। एक गौ-वंश वन्य-विहार रीवा के बसावन मामा नामक स्थान पर तथा एक गौ-वंश वन्य-विहार जबलपुर जिले की कुंडम तहसील में गंगईवीर जंगल परिक्षेत्र में निर्मित होने जा रहा है। इसी प्रकार जिला सीहोर के देलावाड़ी स्थान पर भी गौ-वंश वन्य विहार निर्माण की प्रक्रिया जारी है। हमें विश्वास है सरकार की नीति, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इच्छा शक्ति तथा मध्यप्रदेश गौ-संवर्धन बोर्ड की तत्परता से प्रदेश में गौ-वंश के संरक्षण एवं संवर्धन का अनुकूल वातावरण निर्मित होकर सकारात्मक और रचनात्मक ठोस परिणाम आगामी एक-दो वर्षों में स्पष्ट रूप से दिखने लगेंगे।

विश्व प्रवासी पक्षी दिवस-14 मई 2022

पक्षियों को खतरे में डाल रहा प्रकाश प्रदूषण

विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 मई को भारत सहित दुनिया भर के देशों में मनाया जाता है। यह दिन प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों की रक्षा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालने का दिन है। संयुक्त राष्ट्र इस वैश्विक जागरूकता अभियान का समर्थन करने वाले कई संगठनों में से एक है। प्रत्येक मई के दूसरे सप्ताह के अंत में, दुनिया भर के लोग पक्षी उत्सव, शिक्षा कार्यक्रम और पक्षी-देखने के भ्रमण जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन करके विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस (डब्लूएमबीडी) एक वार्षिक जागरूकता अभियान है जो प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इसकी वैश्विक पहुंच है और यह प्रवासी पक्षियों के सामने आने वाले खतरों, उनके पारिस्थितिक महत्व और उनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने में मदद करने के लिए एक प्रभावी उपकरण है। हर साल दुनिया भर में लोग विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाने के लिए पक्षी उत्सव, शिक्षा कार्यक्रम, प्रदर्शनियां और पक्षी-देखने के भ्रमण जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ये सभी गतिविधियां वर्ष में किसी भी समय की जा सकती हैं, क्योंकि वे देश या क्षेत्र अलग-अलग समय पर प्रवास के चरम को देख सकते हैं, लेकिन मई और अक्टूबर में दूसरे शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय समारोहों के लिए मुख्य दिन हैं। दुनिया भर में हर साल कृत्रिम प्रकाश कम से कम 2 फीसदी बढ़ रहा है और यह कई पक्षी प्रजातियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए जाना जाता है। प्रकाश प्रदूषण प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है, जो रात में उड़ने पर भटकाव पैदा करता है, जिससे ये इमारतों से टकरा जाते हैं। उनकी आंतरिक घड़ियों में गड़बड़ी होती है या लंबी दूरी के प्रवास करने की उनकी क्षमता में हस्तक्षेप होता है। प्रकाश प्रदूषण के समाधान आसानी से उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए, दुनिया के अधिक से अधिक शहर वसंत और शरद ऋतु में प्रवास के चरणों के दौरान इमारत की रोशनी कम करने के उपाय कर रहे हैं। इस बढ़ते मुद्दे को हल करने और पक्षियों को सुरक्षित रूप से प्रवास करने में मदद करने के लिए विश्व स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन के तहत सर्वोत्तम दिशा निर्देश भी विकसित किए जा रहे हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की गतिविधियां दुनिया भर के कई अलग-अलग देशों और स्थानों में होती हैं - एक आम अभियान और थीम से एकजुट होती हैं। यदि आप डब्लूएमबीडी के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करने में रुचि रखते हैं, तो अपनी नियोजित गतिविधि को पंजीकृत करें। इस तरह, व्यक्तिगत घटनाओं को दुनिया भर के अन्य लोगों के साथ साझा किया जा सकता है और उन्हें भी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने में मदद मिलती है।

-इंदौर में चार किस्मों के अनुसंधान पर होगी चर्चा

विशेषज्ञ पढ़ाएंगे सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाने का पाठ

» सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के इस माह होंगे दो आयोजन

» दो दशक के बाद होगी समूह बैठक, आएंगे 150 वैज्ञानिक

इंदौर।

कोरोना से राहत के बाद इस माह भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में किसानों के लिए दो बड़े आयोजन होंगे। अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन अनुसंधान परियोजना की दो दिनी 52वीं वार्षिक समूह बैठक इंदौर में 19 साल बाद होगी। बैठक 17-18 मई को मालवीय नगर स्थित सोपा आडिटोरियम में होगी। इसके अतिरिक्त तीन दिनी सोया महाकुंभ का आयोजन 29 मई से खंडवा रोड स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के सभागार में होगा। इसमें प्रत्यक्ष और वर्चुअल माध्यम से एक लाख किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना के कारण पिछले दो वर्ष से बैठक आनलाइन आयोजित की जा रही थी। बैठक में संस्थान के 33 केंद्रों के 150 वैज्ञानिक आएंगे। इसमें अखिल भारतीय एकीकृत सोयाबीन अनुसंधान परियोजना के देशभर में विभिन्न समन्वय केंद्रों द्वारा 2021 में किए गए अनुसंधान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। इस बार सोयाबीन की चार नई किस्मों के अनुसंधान की समीक्षा होगी। इसके बाद इन किस्मों के उपयोग की अनुशंसा होगी। दो दिन में आठ सत्रों में अलग-अलग विषयों पर चर्चा होगी।

सोया महाकुंभ में आएंगे किसान

तीन दिनी सोया महाकुंभ 29, 30 और 31 मई को होगा। इसमें सोयाबीन की खेती करने वाले राज्यों से किसान आएंगे। सोयाबीन फसलों की जानकारी देने वाले 150 स्टाल और चित्र प्रदर्शनी लगाई जाएगी। संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. बीयू दुपारे ने बताया कि इसमें प्रदेश के विभिन्न नगरों के साथ महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर-पूर्वी राज्यों से किसान आएंगे।

इस माह सोयाबीन के अनुसंधान पर चर्चा के साथ सोयाबीन के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो आयोजन किए जाएंगे। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सोयाबीन की खेती करने वाले किसान जुड़ेंगे। इसके माध्यम से किसानों को सोयाबीन की नई किस्मों से परिचित कराने के साथ विभिन्न जानकारियां दी जाएंगी।

डॉ. नीता खांडेकर,कार्यवाहक निदेशक, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान

-प्रबंधन ने जारी की शीतकालीन सर्वेक्षण की रिपोर्ट

पेंच में मिली पक्षियों की 33 दुर्लभ प्रवासी प्रजातियां

सिवनी।

पेंच टाइगर रिजर्व में दूसरे चरण में ग्रीष्मकालीन पक्षी सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ हो गया है, जो एक सप्ताह तक चलेगा। पक्षी सर्वेक्षण कार्य वाइल्ड लाइफ एडं नेचर कन्जरवेंसी इंदौर के सहयोग से किया जा रहा है। शुभारंभ के दौरान प्रबंधन द्वारा प्रथम चरण में शीतकालीन सर्वेक्षण की विस्तृत रिपोर्ट का विमोचन किया गया। सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक, पेंच के जंगल में पक्षियों की 251 प्रजातियां पाई गई हैं। इनमें 236 संकटमुक्त प्रजातियां हैं। वहीं 9 प्रजातियों का निकट भविष्य संकट में हैं, जबकि 3 प्रजातियां संकटग्रस्त व अन्य 3 तीन असुरक्षित श्रेणी में पाई गई हैं। सर्वेक्षण में शीतकाल के दौरान पेंच में 33 दुर्लभ प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां पाई गई हैं, जो प्रबंधन के लिए खुशी का विषय है। सर्वे में जलस्रोतों के आसपास रहने वाली 65 प्रजातियां पाई गई है।

ई-बर्ड एप्लीकेशन में दर्ज हो रहा डाटा

ग्रीष्मकालीन सर्वेक्षण में हिस्सा लेने विभिन्न प्रांतों के 54 स्वयंसेवक पेंच टाइगर रिजर्व पहुंचे हैं, जो वन अमले के साथ कोर व बफर के सभी 9 वन परिक्षेत्रों में जंगल के भीतर सघनता पूर्वक भ्रमण कर ग्रीष्म ऋतु में उपस्थित पक्षियों की प्रजातियों की पहचान कर उनका डाटा ई-बर्ड एप्लीकेशन में मोबाइल से दर्ज करेंगे। अलग-अलग दल चिंहित बीट में जाकर सुबह से शाम तक सर्वे का काम करेगा। सर्वेक्षण पूरा होने पर सर्वेक्षकों द्वारा दर्ज डाटा को संकलित कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर पेंच प्रबंधन को सौंपी जाएगी।

शीतकालीन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी

27 से 30 जनवरी 22 तक पेंच टाइगर रिजर्व में शीतकालीन पक्षी सर्वेक्षण का कार्य वाइल्ड लाइफ एडं नेचर कन्जरवेंसी इंदौर के सहयोग से कराया गया था। इसमें 9 राज्यों के 69 पक्षी विशेषज्ञों ने भाग लिया था। पेंच टाइगर रिजर्व की सभी 9 कोर व बफर परिक्षेत्रों में 35 दलों ने 11 बेस कैम्प बनाकर सर्वेक्षण का कार्य किया था। इसमें सर्वेक्षकों के साथ स्थानीय मैदानी अमले ने रुचि पूर्ण तरीके से भाग लेकर सर्वेक्षण कार्य में हिस्सा लिया था। सर्वेक्षण से प्राप्त नतीजों पर विस्तृत रिपोर्ट ग्रीष्म कालीन पक्षी सर्वेक्षण के शुभारंभ के दौरान क्षेत्र संचालक अशोक कुमार मिश्रा द्वारा जारी की गई। इस दौरान डिप्टी डायरेक्टर रजनीश सिंह, एसडीओ बीपी तिवारी, पेंच अधीक्षक आशीष पांडे के अलावा सर्वेक्षण कर रही संस्था के सदस्य मौजूद रहे।

तूफान ने उजाड़े हापुस के बाग किसानों की जुगत से आई जान

इंदौर।

आम के पौधे को पेड़ बनने और फल देने में 10 से 12 वर्ष लगते हैं। हम जैसे कितने ही कृषक आम की फसल पर ही निर्भर हैं। 2021 में मई माह में आए तूफान ने फलों से लदे कई पेड़ गिरा दिए। हरेक बगीचे के 10 से 15 प्रतिशत पेड़ धराशायी हुए। हमारे सामने यही विकल्प था कि या तो हम नए सिरे से पौधे लगाएं या कोई तकनीक अपनाकर जोखिम उठाएं। हमने तकनीक को चुना और टूट चुके पेड़ों को फिर हराभरा करने की योजना बनाई जो रंग लाती नजर आ रही है। यह कहना है रत्नागिरी के आम उत्पादक सचिन वैद्य का, जो हापुस आम लेकर इंदौर में आयोजित मैंगो जत्रा में आए हैं। ढक्कनवाला कुआ के समीप ग्रामीण हाट बाजार में शुरू हुआ मैंगो जत्रा रत्नागिरी और देवगढ़ के हापुस आम से लोगों को लुभा रहा है। सचिन बताते हैं कि 2020 में लाकडाउन से आम की बिक्री पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और 2021 में तूफान से करीब 10 से 15 प्रतिशत फसल बिगड़ी। गिरे पेड़ों की हमने छंटाई की और उन्हें सहारा देकर जितना संभव हुआ, खड़ा किया।

आधा हो गया खर्च- केंचुए की खाद और जीवामृत खाद (गोबर, गौमूत्र, बेसन, गुड़ और खेत की मिट्टी से तैयार खाद) इनमें डाली। इसका परिणाम यह हुआ कि वे पेड़ पनप चुके हैं। यदि पौधा लगाते तो 10 से 12 वर्ष बाद फल आता, लेकिन इस तकनीक से तीन से चार वर्ष में ही फल आना शुरू हो जाएंगे। यह जैविक खाद हमने आम के अन्य पेड़ में भी डाली। जिससे खर्च आधा और उत्पाद डेढ़ से दो गुना हो गया।

लाकडाउन में भी बेचा आम

देवगढ़ से आए रामचंद्र करंदीकर बताते हैं कि लाकडाउन के वक्त जब आम की बिक्री भी बाजार में प्रतिबंधित हो गई तो हमने तकनीक का सहारा लिया और उन ग्राहकों से संपर्क साधना शुरू किया जो हमसे पहले से आम खरीदते आ रहे थे। उन ग्राहकों को हमने विशेष अनुमति पत्र के जरिए हापुस आम पहुंचाना शुरू किया। जब बाजार में दूसरे फल उपलब्ध नहीं थे तब हम हापुस आम लोगों को घर पहुंचा रहे थे। इस दौरान कीमत हमने गत वर्षों वाली ही रखी। इसका लाभ यह हुआ कि हमारा माल बचना तो दूर बल्कि कम पड़ गया।

120 टन हापुस आया इंदौर

मराठी सोशल ग्रुप द्वारा आयोजित मैंगो जत्रा में इस बार रत्नागिरी और देवगढ़ के 24 उत्पादक हापुस आम लेकर आए हैं। 300 रुपए दर्जन से 1300 रुपए दर्जन की कीमत वाले हापुस आम यहां लाए हैं। सोशल ग्रुप के राजेश शाह के अनुसार इस बार करीब 120 टन हापुस आम इंदौर आया है। इसके अलावा यहां 26 अन्य स्टाल लगाए गए हैं जिसमें मध्यम और सूक्ष्म रूप के उद्योग को अपने उत्पाद की पहचान बनाने के लिए मंच दिया जा रहा है। इन 26 में से 11 स्टाल सामान्य उत्पादों के, नौ स्टाल महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों के और छह स्टाल इंदौर के जायके के हैं।

-मप्र स्टार्टअप सम्मेलन में शामिल हुए सैकड़ों युवा उद्यमी

ड्रोन के जरिए किसानों की समस्या हल कर रहे इंदौर के प्रयास

इंदौर। आवश्यकता ही अविष्कार की जननी है और छोटी-छोटी जरूरतों को पहचानकर युवाओं ने ऐसे वैचारिक अविष्कार किए जिनसे न केवल वे सफलता की इबारत लिख रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। इंदौर में आयोजित मप्र स्टार्टअप सम्मेलन में ऐसे सौ से अधिक युवा अपने नवीन विचारों के साथ शामिल हुए हैं। इनके स्टार्टअप और सफलता की कहानियां यहां आए हजारों युवा और विद्यार्थियों को करियर की नई राह दिखा रही है।

इंदौर के प्रयास सक्सेना ने किसानों की समस्या सुलझाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया। वे बताते हैं कि हमें शुरुआत में पैसों की जरूरत थी तो स्टैंडअप इंडिया योजना के तहत लोन भी मिल गया था। हम ड्रोन बेचने के बजाए सेवा प्रदाता हैं। एक एकड़ में कीटनाशक का छिड़काव 500 रुपए में होता है। ड्रोन के कारण किसानों को हाथों से छिड़काव नहीं करना पड़ता है। कीटनाशक का छिड़काव करते हुए किसानों के हाथ खराब होते थे, पैदल चलने से फसल को भी नुकसान पहुंचता था और कीटनाशक के कारण नशे या अन्य साइड इफैक्ट भी होते थे। मगर ड्रोन के कारण न सिर्फ समय की बचत होती है बल्कि पूरे खेत में एक जैसा छिड़काव होता है। जो किसान ड्रोन नहीं खरीद सकते, वे भी इस सेवा का इस्तेमाल कर फायदा ले रहे हैं। प्रयास बताते हैं कि वे पूरे मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अब इस स्टार्टअप की लोकप्रियता बढ़ी है तो महाराष्ट्र से भी किसान बुलाने लगे हैं।

शिवपुरी में पर्यटकों के लिए लगाए जाएंगे लग्जरी टेंट

टाइगर के साथ में बनेगा चीतल-कृष्णमृग का बाड़ा

दिल्ली की बैठक में पार्क के अफसरों ने प्रस्तुत किया नया लेआउट

खेमराज मौर्य। शिवपुरी

माधव राष्ट्रीय उद्यान में पिछले कुछ सालों में लगातार पर्यटकों की संख्या कम हुई है। कोरोना काल के बाद तो यहां एक भी विदेशी सैलानी नहीं आया है। अब यहां पर पर्यटकों को फिर से आकर्षित करने की पूरी उम्मीदें टाइगर प्रोजेक्ट पर ही टिकी हुई हैं। राष्ट्रीय उद्यान का मूल कार्य वन्य जीव सरंक्षण है, लेकिन यहां आने वाले पर्यटकों को अच्छा अनुभव देने के लिए अब पर्यटन की दृष्टि से भी माधव राष्ट्रीय उद्यान को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके चलते टाइगर प्रोजेक्ट के लेआउट में थोड़ा बदलाव किया है। मई के प्रथम सप्ताह में दिल्ली में हुई बैठक में पार्क के अधिकारियों ने नया लेआउट प्रस्तुत किया है। इसमें टाइगर के बाड़े के साथ अब एक और बाड़ा बनाया जाएगा। इसमें चीतल और कृष्णमृग रहेंगे। दोनों बाड़ों के बीच महज 50 मीटर की दूरी ही होगी। यह निर्णय इसलिए लिया गया है जिससे यहां साइट सीन के लिए आने वाले पर्यटकों को टाइगर के साथ अन्य वन्यजीव भी दिखाए जा सकें। यह लेआउट दिल्ली के उच्च अधिकारियों द्वारा स्वीकृत करने के साथ ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके पहले तक सफारी में लाए जाने वाले टाइगर के लिए सिर्फ एक बाड़ा ही प्रस्तावित था। पर्यटकों की संख्या को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन ने इस नए बाड़े को लेआउट में शामिल किया है। इसके साथ ही पर्यटकों को यहां आकर्षित करने के लिए कई नई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। जल्द ही राष्ट्रीय उद्यान के अंदर 25 लग्जरी टेंट लगाए जाएंगे जिससे पर्यटक नाइट सफारी का लुत्फ भी उठा सकेंगे और रात जंगल में बिता सकेंगे। इसके लिए निधि स्वीकृत होते ही टेंट ऑर्डर कर दिए जाएंगे। पार्क प्रबंधन ने निधि के लिए कागजी कार्रवाई भी कर दी है।

टेंट लगेंगे जंगल के अंदर

प्रारंभिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान में 25 टेंट लगाए जाएंगे। इसमें 10 टेंट सेलिंग क्लब पर लगाने की योजना है जिससे पर्यटक रात में रुककर सेलिंग क्लब का आनंद भी ले सकें। शेष 15 टेंट के लिए जंगल में अन्य जगह चिन्हित की जा रही हैं। जंगल में लगने वाले टेंटों के चारों ओर फेंसिंग की जाएगी। साथ ही यहां पर एक सुरक्षा की दृष्टि से एक चौकीदार भी रखा जाएगा। टेंट में रुकने वाले मेहमानों को भोजन भी पार्क प्रबंधन उपलब्ध कराएगा। कूनो में इस तरह की व्यवस्था पहले से है। यह भी कुछ इसी तरह की होगी।

चांदपाठा झील को करेगा शुद्ध

राष्ट्रीय उद्यान में आने वाली चांदपाठा झील में फब्बारे लगाने की योजना पर भी काम शुरू किया गया है। अधिकारी यहां पर म्यूजिलक फाउंटेन लगाना चाहते थे, लेकिन वन्य जीव होने की वजह से यहां संगीत या रोशनी वाला फब्बारा नहीं लगाया जा सकता है। इसके लिए यहां पर ऐसा फब्बारा लगाया जाएगा जो दिखने में आकर्षक हो, लेकिन तेज रोशनी न करता हो। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जो भोपाल में उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा। यह ऐसा फब्बारा होगा जो झील के ऑक्सीजन के स्तर को भी बढ़ाएगा और पानी को शुद्ध करेगा।

हर साल घट रही पर्यटकों की संख्या

हर साल राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों की संख्या कम हो रही है। विदेशी पर्यटक तो यहां कम हो ही रहे हैं। साथ ही घरेलू पर्यटकों का रूझान भी कम हो रहा है। इस बात को देखते हुए उद्यान में प्रवेश शुल्क भी आधा कर दिया गया है। साथ ही अब यहां पर सुविधाएं बढ़ाने की पहल की जा रही है जिससे पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। इसके चलते यहां जल्द ही नाइट सफारी, कैंपिंग, नाइट स्टे, ट्रैकिंग जैसी गतिविधियां शुरू की जाएंगी।

साल	देशी पर्यटक	विदेशी पर्यटक
2006-07	1255	137
2007-08	27243	91
2008-09	30919	77
2009-10	27069	103
2010-11	27131	110
2011-12	26276	64
2012-13	26452	78
2013-14	28284	37
2014-15	22416	22
2015-16	16111	04
2016-17	20405	39
2017-18	10441	32
2018-19	17126	28
2019-20	15536	09
2020-21	13039	00

- गत दिनों बैठक में नया लेआउट प्रस्तुत किया है। इसमें दो बाड़े शामिल किए हैं। जिसमें एक में टाइगर रहेगा और दूसरे में शाकाहारी जीव होंगे। जब पर्यटक आएंगे तो उन्हें दोनों देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। टेंट के लिए पूरी योजना तैयार है। इसकी राशि स्वीकृत होते ही ऑर्डर कर दिया जाएगा।
  अनिल सोनी, एसीएफ माधव राष्ट्रीय उद्यान
- राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव सरंक्षण के साथ पर्यटकों की संख्या बढ़ाने पर भी काम कर रहे हैं। टाइगर प्रोजेक्ट भी प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है। कई योजनाएं पाइपलाइन हैं जिससे राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा।
  सीएस निनामा, सीसीएफ

कूनो में मिली दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियां

» राष्ट्रीय उद्यान में करवाया गया बर्ड सर्वे

इधर, श्योपुर के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में करवाए गए बर्ड सर्वे में दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियां मिली हैं। कूनो में इंदौर की संस्था वन्यजीव और प्रकृति संरक्षण द्वारा कूनो पार्क में करवाए गए बर्ड सर्वे में 200 प्रजातियों का पता लगा है। इनमें 12 दुर्लभ प्रजाति के पक्षी हैं। दुर्लभ पक्षियों में एल्पाइन स्विफ्ट, यलो लेग्ड बटनक्वेल, लांग टेल्ड मिनवेट, कॉमन ग्रास होपर, वार्बलर, डस्की वार्बलर, स्मोकी वार्बलर, इण्डियन स्पॉटेड क्रीपर, साइबेरियन रूबीथ्रोट, ब्ल्यू केप्ड रॉक थ्रश, ग्रे बुशचट और व्हाइट केप्ड शामिल हैं। डीएफओ पीके वर्मा ने बताया कि देश में भी इन पक्षियों की प्रजातियां बमुश्किल ही मिलती हैं। लगभग 70 लोगों की टीमों ने 44 सर्वे रूट पर पक्षी सर्वे किया। उन्होंने बताया कि सर्वेक्षण के दौरान 4 प्रजाति की भारतीय चित्तीदार लता, फोर्कटेल ड्रोंगो कोयल, स्ट्रीक थ्रोटेड वुड पीकर, ब्लैक फ्रेंकोलिन, सिरकीर मल्कोहा, क्रेस्टेड ट्री स्विफ्ट, ग्रे नेक्ड बंटिंग, सफेद पेट वाला मिनीवेट, मार्शल इओरा सहित 174 प्रजाति के पक्षी मिले हैं। कूनो पार्क में पक्षी सर्वेक्षण में लगभग 200 प्रजाति के पक्षी मिले हैं।

मध्य प्रदेश में तवा और बाणसागर बांध से गाद निकालने की चल रही तैयारी

बांधों से गाद निकालने से पहले भंडारण का आकलन कराएगी सरकार

भोपाल। संवाददाता

मध्य प्रदेश सरकार पहली बार राज्य के दो बड़े बांध (तवा और बाणसागर) से गाद (सिल्ट) निकालने की तैयारी कर रही है। इसके लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की जानी है, लेकिन इससे पहले सरकार यह पता लगाएगी कि बांधों में गाद और रेत का कितना भंडार है और इससे हर वर्ष कितना राजस्व मिल सकता है। पहली बार ऐसी कंपनी को ठेका दिया जाएगा, जो भंडारण का आकलन कर वास्तविक स्थिति बता सके। इसके बाद इंदिरा सागर और रानी अवंतीबाई सागर (बरगी) बांध से भी गाद निकाली जाएगी। बांधों से निकलने वाली गाद का उपयोग खेतों में खाद के रूप में होगा, तो रेत निर्माण कार्यों में उपयोग की जा सकेगी। प्रदेश में छोटे-बड़े मिलाकर 252 बांध हैं। उनके निर्माण के बाद से अब तक उनकी गाद नहीं निकाली गई है। नदी-झरनों से बहकर आने वाली मिट्टी से भी बांध भर रहे हैं और उनका जल भराव क्षेत्र कम हो रहा है। सरकार बांधों की जल भराव क्षमता बढ़ाने पर काम कर रही है।

आकलन की समस्या अब दूर- करीब आठ महीने पहले बांधों से गाद निकालने का निर्णय लिया गया। जल संसाधन विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है, लेकिन बांधों में गाद के भंडारण के सही आकलन को लेकर समस्या है। किसी को अंदाजा भी नहीं है कि बांधों से कितनी गाद और रेत निकल सकती है। विभाग निविदा निकालकर किसी कंपनी को काम सौंपेगा। उसे पहले बांध में गाद और रेत के भंडारण की स्थिति का आकलन करना होगा।

किसानों को बेची जाएगी गाद

कंपनी चाहे तो आगे भी काम कर सकेगी। इससे विभाग भविष्य में होने वाली नीलामी में बोली के लिए सही दर तय कर पाएगा। वर्तमान में आकलन है कि तवा और बरगी बांध से निकलने वाली गाद से सरकार को 50 करोड़ रुपए सालाना मिलेंगे। बांधों से निकलने वाली गाद अच्छे उर्वरक का काम करती है इसलिए जो कंपनी ठेका लेगी, वह गाद निकालकर किसानों को बेच सकेगी।

यूरिया-डीएपी के इंतजाम करने में जुटी मप्र सरकार

भोपाल। प्रदेश में खरीफ फसलों के लिए किसानों को यूरिया, डीएपी सहित अन्य खाद की कमी न आए, इसके लिए सरकार तैयारियों में जुट गई है। तीन लाख 53 हजार टन खाद का भंडारण किया जा चुका है। खरीफ सीजन के लिए केंद्र सरकार ने 25 लाख टन खाद उपलब्ध कराने पर सहमति जताई है। प्रदेश को पिछले साल केंद्र ने 12.16 लाख टन यूरिया, छह लाख तीन हजार टन डीएपी और एक लाख 63 हजार टन एनपीके खाद की आपूर्ति की थी। इसे देखते हुए इस बार 25 लाख टन से ज्यादा खाद की मांग का प्रस्ताव भेजा गया था। केंद्र सरकार ने 13 लाख टन यूरिया, दस लाख टन डीएपी और दो लाख टन एनपीके की आपूर्ति पूरे सीजन में करने पर सहमति जताई है।

- खरीफ फसलों की अभी से सताने लगी चिंता
- तीन लाख 53 हजार टन खाद का किया भंडार
- केंद्र ने 25 लाख टन खाद देने पर भरी हामी

अग्रिम भंडारण में नहीं लगेगा ब्याज

सरकार ने अग्रिम भंडारण योजना के तहत दो लाख 66 हजार टन यूरिया, 73 हजार टन डीएपी और 13 हजार टन एनपीके का भंडारण करके किसानों को वितरण प्रारंभ कर दिया है। अब तक एक लाख 31 हजार टन खाद किसानों को वितरित किया जा चुका है। अग्रिम भंडारण योजना में किसानों से ब्याज नहीं लिया जाता है।

अब नहीं बिगड़ेगी व्यवस्था

इधर, कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को 70 प्रतिशत खाद उपलब्ध कराने का प्रावधान है। जैसे-जैसे खाद आती जाएगी, वैसे-वैसे उसका वितरण किया जाएगा। इस बार कोशिश यही है कि किसानों को सीजन के समय खाद के लिए परेशान न होना पड़े। दरअसल, पिछले डीएपी और यूरिया को लेकर कुछ जिलों में आपूर्ति व्यवस्था गड़बड़ा गई थी और सरकार को नकद विक्रय केंद्रों की संख्या बढ़ानी पड़ी थी।

दुग्ध संघों में रोजाना 6.75 लाख लीटर हो रही आवक, मांग 10 लाख लीटर

प्रदेश में दूध का उत्पादन बढ़ा पर छह दुग्ध संघों के पास टोटा

भोपाल। संवाददाता

प्रदेश में दूध का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन भोपाल समेत छह सहकारी दुग्ध संघ इस समय दूध की भारी कमी से जूझ रहे हैं। इनके पास रोज होने वाली आवक 6.75 लाख लीटर तक आकर सिमट गई है।

कभी-कभी तो 6 लाख लीटर दूध ही मिल पा रहा है, जबकि उपभोक्ताओं के लिए 10 लाख लीटर दूध की रोज मांग आ रही है। इसमें से 7.50 लाख लीटर दूध की मांग तरल रूप में आपूर्ति के लिए और बाकी का 2.50 लाख लीटर दूध सांची दही, लस्सी, मावा, पेड़ा, लड्डू, मठा समेत अन्य उत्पाद बनाने के लिए लग रहा है। कमी को पूरा करने दुग्ध संघों ने हर वर्ष की तरह पाउडर का उपयोग शुरू कर दिया है।

ये आवक कम होने के पीछे गर्मी में दूध की पैदावर कम होना मानते हैं जबकि ऐसा नहीं है। प्रदेश में भरपूर दूध है, लेकिन सहकारी दुग्ध संघ किसानों को अधिकतम 700 रुपए प्रति किलोग्राम फैट की दर से भुगतान कर रहे हैं जो कि गाय का दूध प्रति लीटर अधिकतम 30 रुपए और भैंस का दूध 40 रुपए पड़ रहा है, जबकि निजी कंपनियां इसी दूध का किसानों को प्रति लीटर दो से चार रुपए बढ़ाकर दे रही है। जिसकी वजह से किसान संघों में कम दूध बेच रहे हैं।

गर्मी में बढ़ा देते हैं दाम

अकेले भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पास मई के पहले हफ्ते में तरल रूप में सांची दूध की मांग 3.10 लाख लीटर रोज थी, लेकिन आवक 2.10 लाख लीटर से लेकर 2.20 लाख लीटर ही हो रही थी। आगे यह आवक और गिरेगी। गर्मी के दिनों में गाय व भैंस की दूध देने की क्षमता बारिश व ठंड की तुलना में अपेक्षाकृत कम हो जाती है। यह हर वर्ष होता है, इसलिए गर्मी के दिनों में हर वर्ष दुग्ध संघों द्वारा किसानों से खरीदे जाने वाले दूध के दाम बढ़ा दिए जाते हैं।

मप्र में इस तरह बढ़ रहा दूध का उत्पादन

वर्ष	उत्पादन
2016-17	13,445
2017-18	14,713
2018-19	15,911
2019-20	17,109
2020-11	17,999

नोट: प्रदेश में दूध उत्पादन के आंकड़े पशुपालन विभाग से प्राप्त है, जो हजार टन में है।

फिर दाम बढ़ाने की मांग

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ ने एक मई से खरीदी दाम 680 रुपए से बढ़ाकर 700 रुपए प्रति किलोग्राम फैट किया है। ये दाम दूसरे संघों ने काफी पहले ही बढ़ा दिए थे। किसान हर बार समय पर खरीदी दाम बढ़ाने की मांग करते रहे हैं। इस बार भी गर्मी शुरू होने से पहले दाम बढ़ाने की मांग को लेकर अड़ गए थे। सीहोर समेत अन्य जिलों में तो आठ दिन तक सहकारी समितियों में दूध नहीं बेचा था।

सरकार किसानों को कम दे रही दाम

इतना ही नहीं, किसानों की नाराजगी यह भी रहती है कि बारिश व ठंड में जब उनके पास पर्याप्त दूध होता है तब दाम कम कर दिए जाते हैं। अभी भी जो दाम दे रहे हैं वह निजी कंपनियों की तुलना में कम है। यही वजह है कि निजी कंपनियां मप्र से बड़ी मात्रा में दूध महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में बेच देती है। किसानों को सहकारी संघों की तुलना में दाम भी अधिक देती हैं।

प्रदेश में दूध का भरपूर उत्पादन हो रहा है। कोई कमी नहीं है। जितना दूध हो रहा है उसका 10 से 11 प्रतिशत भी दूध सहकारी संघ नहीं खरीद पा रहे है। ऐसा दुग्ध संघों द्वारा विपणन क्षमता नहीं बढ़ाने के कारण हो रहा है। संघों को नए सिरे से ढ़ांचागत सुधार करने की जरूरत है। सरकार को भी इस पर ध्यान देना होगा।
- सुभाष मांडगे, पूर्व चेयरमैन, एमपीसीडीएफ मप्र

बाजार से खरीदना पड़ेगा दूध पाउडर!

इधर, मध्य प्रदेश के सहकारी दुग्ध महासंघ ने दूध पाउडर का उत्पादन नहीं बढ़ाया तो पोषण आहार के लिए हर साल गर्मी के तीन माह बाजार से ही दूध पाउडर खरीदना पड़ेगा। वर्तमान में दुग्ध महासंघ सात सौ टन पाउडर तैयार करता है और ग्रामीण आजीविका मिशन को सात संयंत्रों में ही 650 टन पाउडर की जरूरत है। इस साल महासंघ दूध पाउडर उपलब्ध नहीं करा पाया, तो मिशन को बाजार से खरीदना पड़ रहा है। सातों संयंत्रों में 130 टन पाउडर की हर माह जरूरत है। बारिश में दूध उत्पादन बढ़ जाता है, तब सभी छह दुग्ध संघों का मांग से ज्यादा दूध मिलता है। उस समय दूध पाउडर तैयार किया जाता है। पोषण आहार का काम पहले ठेकेदार संभालते थे। वे बाजार से पाउडर खरीदते थे। इसलिए दुग्ध महासंघ को भी कभी उत्पादन बढ़ाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। वहीं आजीविका मिशन ने भी पहली बार पोषण आहार का काम हाथ में लिया है, तो मिशन के अधिकारियों को भी जरूरत की भरपाई न होने का अहसास नहीं था। फिर जरूरत का पूरा पाउडर सरकारी संस्था से ही खरीदने का निर्णय ले लिया।

इस अवधारणा में किसान के खेत को ही वाटर शेड माना गया

वाल्मी की नैनो वाटर शेड तकनीक से बढ़ेगा फसल का उत्पादन

भोपाल। संवाददाता

किसान अपने खेत की भूमि पर प्राप्त हो रहे वर्षा जल को कैसे संरक्षित रख सकते हैं एवं जल का बेहतर उपयोग कर कैसे फसलोत्पादन को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान, वाल्मी ने नैनो वाटर शेड तकनीक का नवाचार किया है। इस तकनीक का उपयोग किसानों द्वारा उनके खेत में किया जा सकता है।

वाल्मी में कृषि संकाय प्रमुख डॉ. रविंद्र ठाकुर बताते हैं कि यदि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर के आंकड़ें देखें तो पाएंगे कि कई देश जहां औसत वर्षा हमारे देश से कम है, जैसे कि इजराइल, वहां बेहतर जल प्रबंधन से भारत की तुलना में अधिक कृषि उत्पादन लिया जा रहा है। वाल्मी द्वारा वाटरशेड डेवलपमेंट (जलग्रहण विकास) पर अब तक माइक्रो वाटरशेड इकाई स्तर पर विकास कार्य किया जा रहा था। अब उसे और सूक्ष्म स्तर पर ले जाकर नैनो वाटर शेड की संकल्पना का प्रयोग किया जा रहा है। परिसर में रिचार्ज कान्सेप्ट तैयार किया है, जो बहुत सफल साबित हुआ है।

किसान के खेत को माना गया वाटर शेड

इस अवधारणा में किसान के खेत को ही वाटर शेड माना गया है एवं इसे तीन भागों में विभक्त कर विभिन्न कार्य किए जाते हैं। पहला जोन है रिचार्जिंग, दूसरा स्टोरेज और तीसरा यूटिलाइजेशन जोन। किसान खेत के एक हिस्से में रन आफ बढ़ा को संरक्षित एवं उपयुक्त निकासी देकर दूसरे हिस्से में बारिश के पानी को स्टोर किया जाता है। तदोपरांत आधुनिक जल उपयोग दक्षता बढ़ाने वाली तकनीकों का उपयोग कर तीसरे हिस्से से बेहतरीन उत्पादन प्राप्त किया जाता है। इसके साथ ही विभिन्न आय मूलक गतिविधियों जैसे मत्स्य उत्पादन, कुक्कुट पालन इत्यादि को समावेशित किया जाता है।

सभी मौसम में मिलेगा पानी

पूरा नियोजन एवं भूमि उपयोग भूमि सामर्थ्य वर्ग के आधार पर किया जाता है। यदि किसान का 10 हेक्टेयर का एरिया है तो भूमि सामर्थ्य वर्ग अनुसार वो लगभग 20 प्रतिशत हिस्से में रिचार्जिंग और 10-20 प्रतिशत स्टोरेज में उपयोग कर तीसरे जोन में मार्डन इरीगेशन तकनीक प्रयोग द्वारा जल का बेहतर उपयोग कर भरपूर उत्पादन प्राप्त कर सकता है। उसे सर्द और गर्म मौसम में भी भूमिगत जल भी प्राप्त हो सकता है।

मप्र में जल उपयोग की क्षमता 30 फीसदी

डॉ. रविंद्र ठाकुर बताते हैं कि हमारे यहां जल उपयोग दक्षता बहुत कम यानी 30 प्रतिशत है। उदाहरण के लिए यदि किसान 100 लीटर पानी यूज करता है तो 70 लीटर पानी व्यर्थ जाता है या बह जाता है। 30 प्रतिशत पानी ही पौधे द्वारा ट्रांस्पिरेशन एवं मेटाबोलिक एक्टिविटीज में उपयोग में आता है। यदि किसान नेनो वाटर शेड तकनीक के जरिए जल उपयोग दक्षता बढ़ा दें, तो कृषि प्रोडक्शन 10 गुना तक या इससे ज्यादा भी बढ़ सकता है। नैनो वाटर शेड या माइक्रो वाटर शेड को कैसे उपयोग में लाया जा सकता है। इसके लिए वाल्मी कंसल्टेंसी सर्विसेज देता है और यदि कोई व्यक्ति अपने खेत में माडल के रूप में इस तकनीक का प्रयोग करना चाहे, तो उसे सलाह दी जाती है।

कृषि कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय की वार्षिक रिपोर्ट से हुआ चौंकाने वाला खुलासा

प्रदेश में 24 फीसदी घटा गन्ने का रकबा

» चार साल की तुलना में मक्का उत्पादन 383 हजार मीट्रिक टन कम

भोपाल। संवाददाता

मध्यप्रदेश में एक साल में कपास और गन्ने की फसल का रकबा कम हुआ है। 2019-20 की तुलना में 2020-21 में गन्ने की खेती 24 और कपास की खेती 9.54 प्रतिशत कम जगह पर की गई। कृषि कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय की वार्षिक रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आए हैं।

मप्र की प्रमुख फसलें सोयाबीन, मक्का और गेहूं हैं। वाणिज्यिक फसलों में कपास, गन्ना, तंबाकू, अफीम, अलसी और तिल हैं। कपास की सबसे ज्यादा खेती निमाड़ क्षेत्र में होती है। इसके बाद मालवा का नंबर आता है। गन्ना मालवा क्षेत्र में ज्यादा होता है। प्रदेश में 2019-20 की तुलना में 2020-21 में कपास और गन्ने की खेती करने का क्षेत्र कम हो गया है। आंकड़ों में देखा जाए तो 2019-20 में गन्ने की खेती 125 हजार हेक्टेयर में की गई, जबकि 2020-21 में यह घटकर 95 हजार हेक्टेयर रह गई। इसमें 24 प्रतिशत की कमी आई। इसी तरह 2019-20 में 650 हजार हेक्टेयर में कपास की खेती की गई थी, जो 2020-21 में घटकर 588 हजार हेक्टेयर रह गई। इसमें 9.54 प्रतिशत की कमी हुई।

वहीं, चार साल की तुलना में प्रदेश में मक्के का उत्पादन 383 हजार मीट्रिक टन कम हुआ।

2017-18 में 4813 हजार मीट्रिक टन मक्का हुआ था, जबकि 2020-21 में यह संख्या 4430 हजार मीट्रिक टन थी। मक्का के विपरीत गेहूं के उत्पादन में इसी अवधि में 15 हजार 649 हजार मीट्रिक टन की वृद्धि हुई। 2017-18 में 20 हजार 20

प्रमुख खाद्यान्न फसलों का उत्पादन

(आंकड़े हजार मीट्रिक टन में)

फसलें	2017-18	18-19	19-20	20-21
मक्का	4813	4133	4489	4430
गेहूं	20020	25276	37198	35669
धान	7349	7926	11044	12502

प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन

खेती का क्षेत्र (हजार हेक्टेयर में)

फसल	2017-18	18-19	19-20	20-21	21-22
गन्ना	98	108	125	95	24 फीसदी
कपास	603	455	650	588	9.54 फीसदी
उत्पादन (हजार मीट्रिक टन में)					
गन्ना	543	528	741	544	26.59 फीसदी
कपास	953	879	839	877	4.53 फीसदी

एक साल में 26.59 फीसदी कम हुआ गुड़ का उत्पादन

एक साल में गन्ने (गुड़ के रूप में) का उत्पादन कम हुआ। 2019-20 में 741 हजार मीट्रिक टन गुड़ का उत्पादन हुआ था, जबकि 2020-21 में यह घटकर सिर्फ 544 हजार मीटिक टन रह गया। इसमें 197 हजार मीट्रिक टन यानी 26.59 प्रतिशत की कमी आई। इसी तरह पिछले साल की तुलना में कपास का उत्पादन 4.53 प्रतिशत ज्यादा हुआ है।

बारिश औसत भी नहीं, इसलिए उत्पादन कम

खेती पर मौसम का सबसे ज्यादा असर पड़ता है। प्रदेश में मानसून का सीजन सामान्य जून से सितंबर तक रहता है। प्रदेश में सामान्य औसत बारिश 1024 मिलीमीटर मानी है। 2020 में जून से सितंबर तक 971 मिमी बारिश दर्ज की गई थी, जो सामान्य से 5.20 प्रतिशत कम थी। इसी तरह 2021 में इसी अवधि में 941.6 मिमी बारिश दर्ज की गई जो सामान्य से 8.07 प्रतिशत कम रही।

हरदा-नीमच में शुरू होगा कृषि और उद्यानिकी उत्कृष्टता केंद्र

हरदा। इजराइल के सहयोग से वर्तमान में छिंदवाड़ा और मुरैना में कृषि व उद्यानिकी की खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किए गए। अगले चरण में हरदा के साथ नीमच जिले में भी इस तरह के केंद्र शुरू होंगे। जहां किसान खेती की नवीनतम तकनीकों की जानकारी लेकर कृषि उत्पादन और आय बढ़ा सकेंगे। यहां किसानों को इजराइल की कृषि तकनीकी के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसमें कम पानी से सिंचाई कर अधिक पैदावार करने एवं आय बढ़ाने की तकनीकी के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस संबंध में हाल ही में शहर की होटल में इजराइली दूतावास के एग्रीकल्चर अटैचे येइर एशेल ने हरदा जिले में उद्यानिकी फसलों की संभावना विषय पर प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किया।

भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर तुरंत प्रभाव से लगाई रोक

अब देश के बाहर नहीं जाएगा हमारा गेंहू

भोपाल/नई दिल्ली। गेहूं के बढ़ते दामों को देखते हुए भारत ने इसके एक्सपोर्ट (निर्यात) पर तुरंत प्रभाव से बैन लगा दिया है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक, भारत ने बढ़ती घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के उपायों के तहत गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, इसमें यह भी कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा किसी दूसरे देश की खाद्य जरूरत के लिए निर्यात की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा वो गेहूं निर्यात किए जा सकेगा जिनके आइईसीएलसी जारी हैं, या शिपमेंट के लिए तैयार हैं।

लगातार महंगे हो रहे गेंहू के चलते खुदरा बाजार में आटा महंगा होता जा रहा है। खुदरा बाजार में आटा का औसतन दाम करीब 33.14 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंचा है। बीते एक सालों में आटा करीब 13त्न महंगा हो चुका है। बीते साल 13 मई को आटा 29.40 रुपए प्रति किलो में मिल रहा था।

गेंहू उत्पादन में गिरावट का अनुमान

गेंहू की कीमतों में आने वाले दिनों में और तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। 2021-22 के रबी सीजन में गेंहू का उत्पादन घटने का अनुमान है। सरकार ने खुद उत्पादन के अनुमान को घटा दिया है। इस वर्ष गर्मी के मौसम के जल्दी आने के चलते सरकार ने 111.32 मिलियन टन से उत्पादन के अनुमान को घटाकर 105 मिलियन टन (10.50 करोड़ टन) कर दिया है।

तेल की मात्रा कम होने से किसानों को नहीं मिल रहा भाव

मुरैना में कुपोषित रह गया सरसों का दाना

अवधेश दंडोतिया। मुरैना

जिले में सरसों की फसल इस बार रिकॉर्ड स्तर पर हुई है। विदेशों से आने वाले तेलों पर भारी टैक्स एवं मिश्रित तेलों के उत्पादन पर लगी रोक के कारण इस साल सरसों के भाव पिछले साल की तुलना में एक हजार रुपए क्विंटल ज्यादा होने उम्मीद थी, लेकिन मौसम की मार से सरसों का दाना ऐसा कुपोषित हुआ कि सरसों में तेल की मात्रा कम और भाव पिछले साल से 600 से 800 रुपए कम रह गए। गौरतलब है कि पिछले साल सरकार ने विदेशों से आने वाले पाम आयल, रिफाइंड आयल व अन्य तेलों पर लगने वाले टैक्स में भारी बढ़ोतरी कर दी। इसके अलावा सरसों का तेल भी अब रिफाइंड होने लगा है। इस कारण बीते साल 2021 में सरसों के भाव अप्रत्याशित बढ़ोतरी के साथ 7500 रुपए क्विंटल पहुंच गए। सरसों की खेती में हुए मुनाफे का असर यह हुआ कि मुरैना जिले में बीते साल 7 लाख 63 हजार 280 बीघा जमीन में सरसों की खेती हुई थी, जो इस बार 8 लाख 58 हजार 635 बीघा में हुई है। किसानों ने गेहूं, चना की जगह अपने खेतों में सरसों की बोवनी की।

सरकार को नहीं दिया एक दाना| सरसों तेल की बाजार में मांग को देख किसान ही नहीं, व्यापारियों को भी अनुमान था कि इस साल सरसों के भाव 8000 से 8500 रुपए क्विंटल पहुंचने की उम्मीद थी, पर पहले कड़ाके की ठंड और फिर समय से पहले आई गर्मी की मार फसल पर ऐसी पड़ी की सरसों का दाना कमजोर रह गया। उधर सरकार ने सरसों का समर्थन मूल्य 5050 रुपए क्विंटल रखा है, जो बाजार भाव से 1750 रुपए क्विंटल तक कम है, इसीलिए जिले में एक भी किसान ने सरकार को सरसों का एक दाना भी नहीं बेचा।

पहले ठंड, फिर गर्मी का कहर| सरसों की फसल नवंबर महीने में बोई जाती है। दिसंबर महीने के दूसरे सप्ताह तक इसमें पीले फूल आते हैं, फिर जनवरी महीने से फूलों से फलियां बनकर, फलियों के अंदर दाने बनने लगते हैं। जनवरी महीने के दूसरे सप्ताह में जब फलियों में दाने बन रहे थे तब लगातार 10 से 12 दिन तक अति शीतल दिन (सीवियर कोल्ड डे) रहे। इसका असर यह हुआ कि जिन फलियों में 14 से 15 दाने निकलते हैं, उनमें सरसों के दाने 11 से 12 दाने ही विकसित हो पाए।

बाजार में सरसों के दाम तेल की मात्रा से तय होते हैं। चंबल अंचल में सरसों की गुणवत्ता अच्छी रहती है। यहां की सरसों में 41 फीसद तेल होता है, लेकिन इस बार 39 फीसद ही तेल की मात्रा रह गई है। इसी कारण भाव पिछले साल से कम रह गए हैं।

मनोज अग्रवाल, तेल व्यवसायी, मुरैना

जनवरी-फरवरी का सीजन सरसों के दाने के विकास का होता है। जनवरी में लगातार शीत लहर व कड़ाके की ठंड रहने से फूलों से फली बनने की प्रक्रिया प्रभावित रही। फरवरी में जब फसल पकने का समय होता है, उस समय ही दाने का पूर्ण विकास होता है। फरवरी के अंत में गर्मी औसत से बहुत ज्यादा रही, इस कारण फसल जल्दी पक गई।

डॉ. बायपी सिंह,वरिष्ठ वैज्ञानिक, सरसों राई अनुसंधान केंद्र चंबल

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, राम नरेश वर्मा-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
बैतूल, सतीष साहू-8982777449
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पता:- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)